DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I heard you saying, 'the biggest Minister' .

SHRI G.M. BANATWALLA : You meant, physically.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Yes. He is a sportsman also. I would have meant physically also.

(iii) Need to form a Parliamentary Committee to improve the affairs of Khadi Gramodyog.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): मैं जो मामला उठा रहा हूं, वह बड़ा गम्भीर मामला है और देश के गरीब आदमी से लेकर हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति तक से संबंधित है । मैं चाहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए और इसका उत्तर हमें दिया जाए ।

मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी का ध्यान देश में बिकने वाले खादी वस्त्रों की ओर ले जाना चाहता हूं । हमें खेद के साथ कहना पड रहा है कि आज खादी वस्त्र की पवित्रता के नाम पर भारी शोषण, लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है । पूज्य बापू एवं देश के अन्य निर्माताओं ने कल्पना की थी कि मोटा खाना, मोटा पहनना के दर्शन से किसानों, गरीबों, मजदूरों की समस्या हल होगी, किंतु आज खादी की दुकानों, बिक्री केंद्रो और उनके शो-रूमों में कपड़ों की कीमत देख कर लोगों के होश उड़ जाते हैं । वहां अत्यंत निम्न कोटि की धोती की कीमत 40 रुपया है । महिलाओं की अत्यंत मामूली साड़ी 50 से 60 रु० की है । इससे कहीं ज्यादा अच्छी मिल की धोती 15 रु० और साड़ी 15 से 25 रु० की है । अत्यन्त साधारण कपड़े आठ दस रुपए मीटर से कम नहीं है, जबकि मिलों के इससे बढ़िया कपड़े 5 रुपए से 8 रुपए मीटर हैं ।

मान्यवर, देश-सेवा, बापू के आदेश एवं मातृभूमि की याद दिला कर खादी उद्योग में लगे बुनकरों, सेल्समैनों और रंगने वालों का खुले-आम शोषण किया जा रहा है । खादी दूकान पर लगे लिपिक-कम-सेल्समैन का वेतन 250 रु० से 350 रु० है । परन्तु आश्चर्य है कि इसके बाद भी खादी ग्रामोद्योग को घाटा ही घाटा होता है ।

अतः मैं आग्रह करूंगा कि तत्काल खादी ग्रामोद्योग में लगे उत्पादकों, सेल्समैनों, अफसरों, हर कोटि के लोगों के वेतन तथा खादी उत्पादन के मूल्यों एवं बिक्री मूल्यों की समीक्षा कराने के लिए एक संसदीय कमेटी बनाई जाए और इसमें सुधार ला कर खादी भावनाओं की रक्षा की जाए ।

(iv) Fall in procurement of Government Supplies from Small Scale and Cottage industries due to insistence by certain departments on I.S.I marked goods.

*SHRI D S.A. SIVAPRAKASAM (Tirunelveli) : Government of India has formulated the policy of procuring the requirement of 104 products from the small scale and cottage industries sector and orders have also been issued in this regard But this is not being implemented effectively. The P and T Department, the Defence Department and the Railway used to purchase Khadi worth Rs. 4 crores per annum from K.V.I.C. Now it has come down to Rs. 1 crore per annum, the defence department is also to buy beedis for the Armed Forces from handmade sector. A large section of our society is engaged in cottage and small units ; they have to get assured market for their products. Now the Depattments are insisting on ISI marks for these products. The big industrialists who have invested huge sums may be able to get

*The original speech was delivered in Tamil